and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 4) Bill, 1976, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 11th May, 1976, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

SIXTEENTH REPORT

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar): I beg to present the Sixteenth Report of the Committee on Government Assurances.

11.04 hrs

WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Raghunatha Reddy on the 18th May, 1976, namely:—

"That the Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The time allotted for this Bill is two hours; time alredy taken is thirty minutes, the balance is one hour and thirty minutes.

श्री राम सिंह भाई (इंदौर) : श्रीमन्, जो संशोधन सदन में लाया गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने यह ठीक ही कहा था कि यह संशोधन निर्विवाद है और इस पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है । दर असल चीज बहुत अच्छी है, इसमें आलोचना करने की कोई गुंजायश नहीं है--इस बात को मैं हृदय से मानता हूं । फिर भी कुछ बातें इसके बारे में कही गई है जिनपर मंत्री जी को थोड़ा विचार करना चाहिए । इस मामले में मेरा जो विरोध है वह केवल एक ही है । जब से वेतन बढने लगीं और वेतन के साथ साथ प्राइसेज बढ़ने लगे और उस समय 5 सौ रुपए से ज्यादा भी श्रमिकों के वेतन हुए तो उसी समय कंसल्टेटिव कमेटी में हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि ई एस आई और कम्पनसेशन एक्ट में संशोधन करने की बहुत आवश्यकता है । जब 5 सौ रुपये से ज्यादा रकम मजदूरों को मिलती है और एक्सीडेंट होते हैं, उनकी जान भी जाती है तो उनको मुआविजा नहीं मिलता है । यह सवाल जनवरी, 1974 में उठा था । उसका कारण यह था कि अहमदाबाद में ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसके अन्तर्गत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एवरेज पर वर्कर 50 रुपए बढ़ गए । इसी तरह से बम्बई में भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसके अन्तर्गत एवरेज पर वर्कर 50 रुपए बढ़ गए । यह मैं डीयर्नेस एलाउन्स की बात नहीं कर रहा हूं । उनके बेसिक वेतन में ही इतनी बढ़ोतरी हुई । इसी तरह से साउथ इंडिया में सारा डीयर्नेस अलाउन्स का रेट चेंज किया गया । इस तरह वहां भी 5 सौ से ज्यादा मिलने पर जो लोग दुरघटना के कारण मरे उनको मुआविजा नहीं मिला मैंने इस सवाल को बार बार उठाया ।

उसके बाद अब यह संशोधन यहां पर आया है । माननीय मंत्री जी ने अपने एस्टेटमेंट में कहा है कि इसका अमल अक्तूबर, 1975 से किया जायेगा । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अक्तूबर, 1975 से ही

[श्री रामसिंह भाई]

इस पर अमल करने में क्या लाजिक है। अक्तूबर, 1974 में श्रमिकों का ज्यादा से ज्यादा औसत वेतन था जबकि कंज्यूमर कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स 335 तक पहुंच गया था जोकि अक्तूबर, 1975 में घटकर 316 ही रह गया। तो मेरा निवेदन है कि जब 335 कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स हुआ उसके पहले जिन श्रमिकों को 5 सौ रुपए से कम वेतन मिलता था और वे वर्कमेन कम्पेन्सेशन ऐक्ट में कवर होते थे लेकिन दूसरे महीने ही कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स बढ़ जाने के बाद 501 रुपया या अधिक हो जाने के बाद उसकी मौत हो गई हो तो उसको कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा। यह गल्ती किसकी है? वह आदमी वही काम कर रहा है, उसी पोस्ट पर है, उसी स्केल में हैं, किसी तरह का कोई फक नहीं आया है, आज उसकी मौत होती है काम करते हुए तो उसे मुआविजा मिलता है लेकिन कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स में कुछ प्वाइन्ट बढ जाने की वजह से कल उसका वेतन बढ़ गया और उसी काम को करते हुए उसकी मौत होतो है तो उसको मुआविजा नहीं मिलता है। मेरा निवेदन यह है कि जब यह मामला आपके सामने था तो आपको बहुत पहले से ही इसमें संशोधन करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो अब इसको उसी पिछले समय से लागू करना चाहिए जब कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स बढने लगा था और जिन लोगों के ऊपर यह ऐक्ट लागू होता था अगर उनकी मौत हुई है तो उन्हें इसका मुआविजा मिलना चाहिए।

श्रीमन्, मेरे मन में प्राइम मिनिस्टर का बड़ा आदर है जिस टाइम पर मैं ने उन को बताया कि ई०एस०आई० में ऐसा हाल है और इस में संशोधन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी लिख कर दो और मैं ने उन के कार्यालय में ही बैठ कर लिख कर दिया और वह प्रधान मंत्रीजी द्वारा माननीय मंत्री जी के पास भी भेजा गया।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लेबर मिनिस्ट्री पर इस समय बहुत बड़ी जवाबदेही है लेकिन इस सब को देखते हुए यह मिनिस्ट्री पहले से आधी भी नहीं रही। मैं समझता हूं कि इस को डबल होना चाहिए था। पहले लेबर मिनिस्टर के साथ दो दो डिप्टी लेबर मिनिस्टर थे लेकिन आज इतना स्टेट्स गिर गया है कि एक स्टेट मिनिस्टर हैं। मैंने जो दो डिप्टी मिनिस्टर और एक लेबर मिनिस्टर की बात कही, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब सैकन्ड फाइव इयर प्लान को अमल में लाया जाना था। अब तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहले से काफी बढ गया है, इसलिए लेबर का कैबिनट मिनिस्टर होना चाहिए और क्योंकि इस विभाग की जिम्मेदारी और जवाबदेही काफी बढ गई है, इसलिए साथ में दो डिप्टी मिनिस्टर भी होना चाहिए जो ई०एस०आई० और वर्कमैन कम्पेसेंशन को स्वतंत्र डील करे। आप यह देखें कि मेरे जैसे पुराने सफेद बाल वाले लोग तो श्रम मंत्रालय से चले गये है और जब जिन की रेखें नहीं आई हैं वे लोग आ गये हैं और उन को समझने में अभी बहुत समय लगेगा। कल मेरे एक मित्र ने आलोचना की थी लेकिन उन्हे पता नहीं क्या संशोधन किया है, मैं यह समझता हूं कि जो संशोधन किया गया है वह ठीक ही किया गया है और शेड्यूल में भी बड़े अच्छे परिवर्तन किये गये हैं। इस मे कोई शक नहीं है। आप ने कम्पेसेशन की रकम जो पहले मिलती थी, उस का तीन गुना कर दिया है और इस के लिए मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा किया। आप ने वेतन की रकम 500 से बढ़ा कर 1000 कर रहे हैं और जिस को पहले 14,000 रुपये कम्पेसेंशन मिलता था उस को 42,000 रुपये कर रहे है, इस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा जो एक खास मुद्दा है वह यह है कि अब कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स गिर रहा है और

जब आप वेतन की सीमा बढा रहे हैं, किन्तु जब कास्ट आफ लिविंग बढने से वेतन 500 से अधिक बढ गया था और जो आदमी इसके पहले मर गये है, उन के कम्पेंसशन का क्या होगा ।

अगली बात यह है कि कम्पेंसशन देने में जो डिले होती है, उस के बारे में आप को विचार करना चाहिए । ऐसे मामलों में डिले नहीं होनी चाहिए । एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आज वर्कमैन कम्पेंशन का ट्रेंड बदल गया है और कल जो बात सरदार स्वर्ण सिंह सोखी ने कही थी, वह उन्हे कहनी नहीं आई । सवाल यह है न कि जब व्हिसिल बजती है तो फौरन श्रमिक कारखाने में काम करने के लिए घर से निकलता है और इस इरादे से वह जाता है कि वह वहां काम करेगा । रास्ते में उस की किसी एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है तो उस के घरवालों को कम्पेसेंशन नहीं मिलता । आप कारखाने में जाने और काम करने के बाद घर पहुंचने का टाइम मुकर्रर कर दें और उस समय को काम की हालत माना जाए । इस के लिए आप को कम्पेसेशन एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा कि अगर श्रमिक को काम पर जाते या लौटते समय किसी एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, तो उस को काम पर माना जाए और उसको कम्पेसेंशन दिया जाए । इस वक्त तो प्रोवीडेंट फंड एक्ट के अन्तर्गत फैमिली पेंशन में भी परिवर्तन की आवश्यकता है वह परिवार को उसी हालत में मिलेगी जबकि श्रमिक काम करता हुआ मर जाए । अगर वह रात के 12 बजे तक काम करने वाले दिन मरता है तो फ़ायदा मिलेगा, यदि उस रोज 12 बज कर 1 मिनट पर वह मर जाता है, तो फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी । उसे 12 बजे से पहले ही मरना चाहिए था और अगर नहीं मरता है तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए । इसलिए ऐसे कानून में संशोधन करने की जरूरत है ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी जी ने एक बात और कही थी कि अगर एक पति है और चार पत्नियां हैं, तो कम्पेसेंशन किस को मिलना चाहिए । (**व्यवधान**) इसी प्रकार से एक विवाद यह भी पैदा हुआ एक महिला काम करती थी और उस के दुर्घटना से मरने के बाद दो पति दावेदार पैदा हुए । इन्क्वायरी करने पर यह पाया गया कि जिस से उस महिला की पहले शादी हुई थी, वह तो पहले ही मर चुका था, लेकिन बाद में जिन दो ने कम्पेंसशन पाने के लिए दावा दायर किया, उन दोनों को कम्पेसेंशन नहीं मिला । क्योंकि दोनों ही असली वारिस नहीं थे । ऐसे विषय में कुछ होना चाहिए वह इस एक्ट के अन्तर्गत नहीं किन्तु कौन वारिस हो सकता और कौन नहीं होगा, यह तो दूसरे एक्ट में ठहराया गया है ।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी बहुत सुन्दर कानून लाए हैं और उस में सारी अच्छी बातें हैं और मैं उस का समर्थन करता हूं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ने जो इस को अक्तूबर 1975 से लागू करने की बात की है, उस को कम से कम अक्तूबर 1974 से लागू करना चाहिए । जब सब से अधिक उपभोक्ता अंक पहुंच गया था ।

इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

SHRI B. V. NAIK (Kanara): Mr. Speaker, I welcome this Bill. When we go through the amount of compensation for permanent disablement as well as for death, we think it is a part and parcel of the labour welfare measure and a part and parcel of our welfare measures of which we are talking.

In view of the rise in price and the cost of living index, I think raising of the limit, for eligibility from Rs. 500 to Rs. 1,000 is quite welcome. Any person by whatever name he may be called in this country—a wage earner, a labourer, a salary earner, it would be rather hard to consider a person with an annual income of Rs. 12,000 per annum other than poor. In a country like ours, the per capita income of Rs. 40/- per month, *i.e.*, Rs. 200 per family,

[Shri B. V. Naik]

is considered as a poverty line—giving the whole family an annual income of Rs 2,400, below which the amount falls into the poverty line. I think, a person drawing Rs. 12,000 in the course of the year is a fairly affluent person. Be it as it may, since this category of middle level people in factories and industrial establishment is of very valuable people—in supervision, direction or in technical know-how, we do not grudge. The only thing which we seem to grudge, with very conscientious Labour Minister, is that he has been keeping a blind eye on that section of our labuor population. At least I have been raising this issue time and again.

In response to a starred question which figured here very recently, even the census of the categories of labourers-wage earners like domestic servants, shop assistants, those working in an unorganised industry as a whole, was not made available to us. I hope, to that extent, it will be possible for me to make some impact on our Labour Minister that immediately the census should be taken of those working in an unorganised industry. Some modicum of welfare labour legislation is a must. Leave aside the question of compensation, in case of death, accident or permanent disability, as we are having minimum basic charges in respect of farm labourers, we should have likewise minimum salary for other categories of labourers. We should find out ways and means of implementing the welfare measures for the weakest and the most exploited section of our labour population. This is a must.

The same preparatory work regarding date collection most go on. The other thing that puzzles me is this. Of course, one may say, this does not fali within the ambit of the Labour Ministry, as such. We do not seem to have a sort of a national policy in the case of accidents or death or disability. I see this happening in the ore carrying track from where I come, between Hubli and Karwar. There are accidents taking place; leaving aside damage to national property, somebody or other dies, somebody or other gets maimed and so on. I do not know, who takes care of these people. We have got accident relief in case of rail travel. It is a public sector undertaking which has provided this. We have got relief in case of air travel. But the most accident prone areas are the roads. It is more hazardous to travel by road than by the air. This is because of overcrowding. The hon. Ministers in the treasury benches may not have the opportunity but we MPS have this opportunity to travel by bus of course, by compulsion. Upto 50 per cent of over crowding takes place there. During the summer season you can well imagine the difficulty involved. There are students and others and if any crash takes place you can well imagine the hazards involved. One gets scared, but this is inevitable. Why cannot you have some standard relief here also and this can be sponsored by the Ministry of Labour or some other Ministry to help the kids, children, women, school-going boys and girls, etc. by having a comprehensive legislation that in case they are maimed or some other injuries are there, they will get relief at some standard scales?

रेल एक्सीडेंट के बारे में आप पचास हजार रुपए देते हैं। यहां कम से कम पच्चीस हजार रुपया तो आप दीजिए।

In respect of bus travellers who get killed or maimed this can be done. This is one of the suggestions which i wish to make.

I have looked into the statistical figures on fatal and non-fatal accidents. For this booklet we congratulate the Minister. In 1972 the number of fatal accidents in factories was 655 and in 1973, 647. In 1972 number of non fatal accidents was 2,85,257 and it is more or less the same in the year 1973, that is, 2,80,602. If death in factories during one year is something attributable to his duty, I could say the death by other road accidents etc., would be very much more. It would be about ten times more than

that. Of course this year because of Chasnala tragedy the mine accidents might have been more. In this connection I wish to point out that we do not have the figure regarding permanent disability.

I hope this piece of legislation will be able to do good. But, may I point out one more factor? Will the Minister kindly enlighten us whether in respect of sea-men, in respect of Merchant Navy, there has been a provision for losing of a finger, for losing of a particular limb, according to the contract between the shipowners and the sea-men that, on a fabulous scale, the compensation is provided for? I am not grudging that something is being done because these are workers; these are sea-men, but, what I am saying is why, between workers and non-workers or between different categories of workers, should our country have such an amount of disparity in regard to compensation due to death or fatality or because of disability? Why could we not, in a progressive socialisation of our economy, bring down the disparities? Remove the vested interests or pressure groups who are more effective. (*Interruptions*) I was thinking whether Dr. Sen was ironically laughing. Thank God.

So, why can't we bring down the disparities in regard to benefits or compensations? Here the hon. Minister simply comes forward with a comprehensive policy resolution or decision, not in regard to a blanket order, and you may just say how you are going to reduce the disparities even in the welfare of the labour section, leave aside the disparity that exists, on a vast scale, in our society and how you, as the Ministry, will strive to bring down the disparity that exists within labour? For example, one peon working in a small government office or municipality gets hardly Rs. 150/- whereas, another peon, working on some of the prized posts doing the same peon's job will be getting about five times more than this or some such thing.

On the contrary, the hon. Labour Minister may kindly bring forward a statement and say that, over the years, the disparities between the working forces keep on increasing or you may prove that the disparity continues *status quo* or it goes on reducing. You may prove that. Because of your superior accessto facts and figures, you may kindly prove that between workers and non-workers ,the disparity is not increasing but decreasing.

With these suggestions, complimenting the Minister. I sit down.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन कुछ बातें कहना चाहता हूं । सबसे पहले तो मैं रिपोर्ट आफ दि नेशनल कमीशन आफ लेबर से यह आपके नोटिस में लाना चाहता हूं—

"This Act makes no provision for medical care and treatment which is the greatest need of the worker when he meets with an accident. There is also no provision for rehabilitation to restore the loss in the earning capacity."

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर रेलवे के किसी एम्प्लाईज की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे को नौकरी मिल जाती है । अगर कोई आदमी फैक्टरी में काम करता हो और उसकी डेथ हो जाय तो उसका सक्सेसर जो लड़का है, जो पर मैं बैठा है, उसकी नौकरी की भी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : पार्लियामेंट में काम करता हुआ अगर कोई मेम्बर आफ पार्लियामेंट मर जाय तो उसके लड़के को भी क्या मेम्बरी दे देंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं पार्लियामेंट के मेम्बर की बात नहीं करता लेकिन डिफेंस और रेलवे के अंदर यह कानून बना हुआ है कि उनके अंदर काम करने वाले का यदि स्वर्गवास हो जाय तो उसकी औलाद को काम मिल जायगा ।

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : मौत अगर घर में हो जाती है तब थोड़े कुछ मिलता है। जहां पर वह काम करता है, वहीं पर अगर मौत हो, तभी कुछ मिलता होगा।

श्री मूलचन्द डागा : जहां पर वह काम करता है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके लड़के को नौकरी देने की व्यवस्था है।

आपने कम्पेंसेशन एक्ट में कहा हुआ है :

"Workman means any person (other than a person whose employment is of a casual nature and who is employed otherwise than for the purposes of the employer's trade and business)."

एक आदमी एक कारखाने में दो महीने या तीन महीने काम करता है और उसके बाद एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है तो आप कहते हैं कि वह कम्पेसेंशन पाने का हकदार नहीं है। यह परिभाषा गलत है। जब काम बराबर दोनों करते हैं और जो तीन महीने पहले लगा होता है उसकी मौत हो जाती है तो क्यों आप यह कहते हैं कि वह टैम्पोरेरी था इस वास्ते उसको कम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। इस में संशोधन करने की जरूरत है।

मैंने एक सवाल हाउस में किया था। उस के जवाब में मुझे बताया गया था कि हवाई जहाज का एक्सीडेंट होने की सूरत में पैसेंजर को एक लाख रुपया मिलता है।

"In the event of death of a passenger or....Rs. 1,00,000 if the passenger is 12 or more years of age and Rs. 50,000 if the passenger is below 12."

यह क्या बात हुई ? हवाई जहाज के एक्सीडेंट में उसको एक लाख रुपया और जो फैक्ट्री में काम करता है, उसको इतना कम रुपया फिर चाहे वह पब्लिक सैक्टर की फैक्ट्री हो या प्राइवेट सैक्टर की। रेल एक्सीडेंट में जो मर जाता है उसको आप पचास हजार देते हैं। लेकिन यहां जो मरता है उसको ज्यादा से ज्यादा तीस हजार ही दिया जाता है। यह सब अंतर क्यों आप करते हैं। सरकार की नीति एक होनी चाहिए। हवाई जहाज में सफर करने वाला चूंकि बड़ा आदमी होता है इस वास्ते क्या उसको ज्यादा मिलना चाहिये ? बस एक्सीडेंट में मरने वाले को कुछ भी नहीं मिलता है।

मैंने आपके शैडयूल को पढा है। एक हजार कमाने वाले को 42,000 आप देंगे और जो दो सौ या तीन सौ रुपये महीना कमाने वाला है, उसको आप कम देंगे। जो ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा और जो कम कमाता है उसको कम, यह तुक मेरी समझ में नहीं आता है। मैं कहूंगा कि जो कम कमाता है उसको आपको अधिक देना चाहिये।

वर्कमैन कम्पेंसेशन एक्ट 1923 का है। इसको आप बदले। मंत्री महोदय जब से श्रम मंत्री बने हैं वह बराबर एमेंडमेंटस् लाते रहे है। मजदूरों का फायदा करते रहे हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है वह बहुत लंबा है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। पता ही नहीं लगता है कितने समय में कम्पेंशन मिलेगा सकसैशन सर्टिफिकेट अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से लेना होता है तो उस में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। वहां बड़ा हैरासमेंट होता है। उससे पहले ही फार्म भरवा लिया जाना चाहिये कि उसकी मौत के बाद फलां को कम्पेंसेशन दे दिया जाए।

मैं जाहता हूं कि कम्पेंसेशन की रकम को आप बढाएं। दुर्घटना के बाद उसके लड़के को नौकरी देने की व्यवस्था करें।

एक बात और आपने कही है।

"A small employer in any case finds it difficult to pay compensation in the event of a heavy liability arising out of a fatal accident."

जो छोटी फैक्ट्री चलाता है और जिस में पचास हजार रुपया लगा हुआ है अगर वहां किसी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो आप उसको कहेंगे कि चालीस हजार रुपया इसको दो । अब छोटी इंडस्ट्री चलाने वाला कैसे दे सकता है । उसकी तो फैक्ट्री ही नीलाम हो जाएगी । और भी जो वर्कर उस में काम करते है वे बेकार हो जाएंगे । इस वास्ते इस वर्कमैन कम्पेंसेशन मे एक बात यह भी होनी चाहिये कि अगर कोई छोटा उद्योग चलाता है और वहां मालिक की गलती न हो तो उस के लिए कुछ और व्यवस्था होगी इस एसपैक्ट को भी आपको कंसिडर करना चाहिये ।

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): Sir, I am exteremely thankful to all the hon Members who have extended their wholehearted support to the provisions of this Bill. For the various points that have been raised by some hon. Members, I would respectfully submit to you that as far as the provisions of the Bill before the House are concerned, the discussion falls within a very narrow compass and we are dealing with certain aspects of the workmen's compensation Act. Yesterday. the Hon'ble Member, Shri Ismail, raised the question whether the seamen are covered under the Act. At that time itself I referred to the provisions of the original Act and Schedule-II to the Act covers the seamen and therefore I think Mr. Ismail should be satisfied about it.

The second question which has been raised by Mr. Daga, just now, is about the casual labour. Now the definition of 'workmen' means any person (other than a person whose employment is of a casual nature and who is employed otherwise than for the purposes of the employer's trade or business).....So, it is not merely casual labour but it should also satisfy the condition that he is employed otherwise than the trade or the business of the employer. First, he must be a casual labourer and then he should also not have been employed in any business of the trader or the business of the employer. Then he falls outside the purview of the Act. The mere casual labour who is employed by the business man or the trade of the employer is not excluded from the purview of this Act. There is also a judgement of the Madras High Court in this connection and with regard to the various principles of compensation law regarding this, there is quite a formidable case law both of Indian Courts as well as English Courts. Mr. Daga, as a lawer, must be able to recollect from learned judgements of the various English Courts regarding Workment's Compensation Act. I do not want to go into the question of workmen compensation here.

Another question that has been raised here is about the date on which this Act will come into force, that is, 1st of October 1975. The question raised was that there could be some other day. If we do not give any retrospective effect to this legislation, it can only be prospective and you may kindly recall that after 1st October 1975, unfortunately there had been a number of accidents including the Chasnala accident. Therefore, we thought that we must be in a position to cover all those unfortunate families who have lost their bread-winners sometime in November or December 1975. Therefore, we have chosen 1st October 1975 to give the maximum relief to those persons whose families are suffering now. That is the reason why 1st October 1975 was chosen. There may be difference of opinion that some other date could have been chosen.

With regard to the points raised by Mr. Naik, though most of points raised by him do not fall within the purview of this Bill, I would respectfully

[Shri Raghunatha Reddy]

submit, as far as the compensation is concerned, it is with regard to a worker who is working in a factory and who has been earning livelihood, not only earning livelihood for the family but also who is making a contribution to the national economy and national wealth. That is why we said "having regard to the rise in wages and DA etc., from Rs. 500.00 to Rs. 1,000...." and I quite see the point made by Mr. Naik that those who have got Rs. 1000 per month cannot be necessarily classified as poor people in this country. But whether they are classified as poor people or not, the fact remains that the people or the workmen whatever the designation they may hold, whatever the salary they may be getting, they are making contribution to the growth of the national economy and to the national wealth and to that exent, they must be compensated if any unfortunate accident takes place, death takes place, disability takes place. That is why it has been raised but at the lowest level the highest compensation has been fixed not in terms of quantum but in terms of multiples. When a railway passenger is involved in an accident, he is paid Rs. 50,000 in the case of death. An air passenger is paid Rs. 1 lakh in case of death. It was asked whether this was not a discrimination against the poor people working in factories? So far as I can see, the distinction between the two is this. When a passenger travels by air or rail, he pays for it and he goes by a commercial carrier. There is some kind of a contractual obligation that the commercial carrier would take him safely to the place of destination. So, if there is an accident, he must be paid compensation for not fulfilling that obligation. Here a person working in a factory is drawing his salary and during the course of employment and out of the employment if an accident takes place, he is entitled to compensation. There is no comparison between the principles of compensation contemplated under the Workman's Compensation Act on the one hand and a passenger who travels by rail or air, by a commercial carrier on the other.

These were the few points raised and I have dealt with them. I am extremely grateful to the hon. members who have given their whole-hearted support to the Bill.

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : आप ने यह नहीं बताया कि 1,600 रु० बोनस कमीशन ने जो फिक्स किया था उस को क्यों रिजेक्ट किया है ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: Though the Bonus Act considers Rs. 1600, it will be treated as Rs. 750 for the purpose of computation of bonus. Therefore, we have even fixed it at a higher level here.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now we take up clause-by-clause consideration. There are no amendments. I shall put all the clauses together

The question is:

"That clauses 2 to 4, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.